भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 622

23 जुलाई**,** 2025 को उत्तर देने के लिए

विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास

†622. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, घटक-वार स्वीकृत और विकसित अवसंरचना का घटक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक घटक के अंतर्गत, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, अवसंरचना के विकास के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत स्थापित नई अनुसंधान प्रयोगशालाओं, इनक्यूबेशन केंद्रों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालयों और अन्य वैज्ञानिक सुविधाओं तथा उनकी वर्तमान परिचालन स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वैज्ञानिक अवसंरचना के संतुलित क्षेत्रीय वितरण, विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों में सुनिश्चित करने तथा योजना का योजनाबद्ध रूप से विस्तार करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं/ किए जा रहे हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी विभाग, देश भर में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में विज्ञान धारा योजना का क्रियान्वयन करता है। वैज्ञानिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु, यह योजना प्रतिस्पर्धी आधार पर विभिन्न घटकों जैसे एस एवं टी अवसंरचना सुधार कोष (फिस्ट), विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन (पर्स), परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाएँ (सैफ), परिष्कृत विश्लेषणात्मक एवं तकनीकी सहायता संस्थान (साथी), और नवोन्मेष और उत्कृष्टता हेतु विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (क्यूरी) को सहायता प्रदान करती है। इन घटकों के माध्यम से, आंध्र प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में वैज्ञानिक अवसंरचना विकास हेतु कई परियोजनाओं को सहायित किया गया है।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में विज्ञान धारा के अंतर्गत वैज्ञानिक अवसंरचना के विकास हेतु प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा:

घटक का नाम / कार्यक्रम	**आवंटित धनराशि (करोड़ में)**	**सहायित परियोजनाओं की संख्या**	**सहायित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र**	**सहायित विभागों/ संस्थानों की संख्या**	**सहायित वैज्ञानिक अवसंरचना सुविधाओं की संख्या**
फिस्ट	31.71	27	असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।	27	86
पर्स	65.66	13	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड।	13	81
सैफ	10.00	5	चंडीगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।	5	8
साथी	76.86	4	राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।	4	71
क्यूरी	1.00	3	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	3	23

आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिक अवसंरचना के विकास हेतु प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा:

घटक का नाम / कार्यक्रम	**आवंटित धनराशि (करोड़ में)**	**सहायित परियोजनाओं की संख्या**	**संस्था का नाम और पता**	**सहायित वैज्ञानिक अवसंरचना सुविधाओं का विवरण**
पर्स	3.45	1	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (मानित विश्वविद्यालय), गुंटूर (जिला)	परमाणु बल माइक्रोस्कोप, ईएम स्कैनर और ईएमआई/ईएमसी टेस्ट बेंच, स्पिन कोटर के साथ ग्लव बॉक्स, आरएफ स्पटरिंग, प्रोटोटाइप मशीन, उच्च परिशुद्धता इंकजेट प्रिंटर, विद्युत चुम्बकीय सिमुलेशन उपकरण और सुरक्षा अवसंरचना
क्यूरी	0.42	1	श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरवीएस नगर, तिरुपति	2डी अल्ट्रासाउंड मशीन, एबीजी मशीन, एम्बू बैग रिससिटेटर, कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, यूएसजी मैमोग्राम, इन्फ्यूजन पंप, नवजात शिशु इनक्यूबेटर, ईसीजी मशीन, वेंटिलेटर

(ग) विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत, नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल - समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (निधि-आईटीबीआई) कार्यक्रम प्रोटोटाइपिंग प्रयोगशालाओं और संबंधित सुविधाओं सहित आवश्यक अवसंरचना प्रदान करके नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को सक्रिय रूप से सहायता दे रहा है। इस पहल के तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने असम के एनआईटी सिलचर और त्रिपुरा के एनआईटी अगरतला में निधि-आईटीबीआई की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी, ट्रांसलेशन और नवाचार (टीटीआई) प्रभाग के कार्यक्रम के अंतर्गत, महाराष्ट्र के वीएनआईटी नागपुर और पंजाब के चितकारा विश्वविद्यालय में कृषि अवशेष प्रबंधन पर केंद्रित दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) वैज्ञानिक अवसंरचना के संतुलित क्षेत्रीय वितरण को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) अपने अवसंरचना विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईआईटी, एनआईटी, एम्स, आईआईएसईआर और आईआईएससी सहित केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं की विस्तृत श्रृंखला तथा राज्य विश्वविद्यालयों, स्नातकोत्तर कॉलेजों और निजी शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है। चयन प्रक्रिया को समावेशी बनाया गया है और इसमें क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य के अनुरूप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2022 में पर्स पहल के तहत एक विशेष आह्वान शुरू किया है ताकि पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, और कई मध्य एवं पूर्वी राज्यों जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जा सके, जिससे इन क्षेत्रों के विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अवसंरचना को मज़बूत कर सकें। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखते हुए वंचित क्षेत्रों को लक्षित करने वाला यह दोहरा दृष्टिकोण, देश भर में समावेशी और संतुलित वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डीएसटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

*****